भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3217

2026/03/20 को उत्तरार्थ

विषय: यूरिया की बोरी का वजन कम करने का कृषि लागत पर प्रभाव

3217. श्री रामजी लाल सुमनः

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यूरिया की बोरी का वजन 50 किलोग्राम से घटाकर 40 किलोग्राम करने और नाइट्रोजन की मात्रा 46 प्रतिशत से घटाकर 36 प्रतिशत करने से किसानों को अतिरिक्त उर्वरक खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, जिससे कृषि लागत बढ़ रही है;

(ख) क्या उर्वरक को कम करने के कारण किसानों की उत्पादकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही है; और

(ग) उर्वरक कम करने के क्या कारण हैं, इसके लिए किन-किन स्तरों पर सुझाव लिए गए थे और क्या इसमें किसानों को शामिल किया गया था?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (ग): सरकार वर्ष 2018 से नीम लेपित यूरिया (एनसीयू) को बढ़ावा दे रही है और एनसीयू के 45 किलो बैग की कीमत 242 रुपये है, जिसमें 5% नीम कोटिंग शुल्क और 5% वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) शामिल नहीं है। सरकार ने सल्फर लेपित यूरिया (एससीयू) की कीमत दिनांक 23.01.2026 को अधिसूचित की थी, जो 40 किलो बैग के लिए 254 रुपये (18% सल्फर कोटिंग सहित) है, जिसमें 5% जीएसटी शामिल नहीं है। एनसीयू और एससीयू की अंतिम कीमत समान है, अर्थात कोटिंग और जीएसटी सहित 266 रुपये प्रति बैग।

एनसीयू में 46% नाइट्रोजन होता है, जबकि एससीयू में 37% नाइट्रोजन होता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) ने बताया है कि एससीयू सल्फर कोटिंग के माध्यम से नाइट्रोजन को धीरे-धीरे रिलीज करके कार्य करता है, जिससे पोषक तत्वों की कम हानि होती है और नाइट्रोजन की उपलब्धता फसल की मांग के अनुरूप हो जाती है। इससे उर्वरक उपयोग दक्षता (एफयूई) में सुधार होता है, जो आमतौर पर 50-60% तक होती है, जबकि पारंपरिक यूरिया के लिए यह 30-40% होती है। एससीयू की उच्च दक्षता के कारण, कम मात्रा में यूरिया से समान प्रभावकारिता प्राप्त होने की उम्मीद है, जिसके परिणामस्वरूप उर्वरक उपयोग और कुल इनपुट लागत में बचत होगी और संतुलित एवं सतत पोषक तत्व प्रबंधन को बढ़ावा मिलेगा।

*****